Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

मार्च (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार **3**

- बिहार की बबीता गुप्ता का 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023' के लिये चयन 3
- गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 3
- पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हुआ आयोजन 4
- राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना 5
- प्रदेश के 33 ज़िलों में खुलेंगे खेलो इंडिया के सेंटर 6
- अररिया में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 6
- विश्वस्तरीय बनेगा बिहार का मुज़फ्फरपुर रेलवे जंक्शन 7
- बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 8
- बिहार में 557 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मिली प्रारंभिक हरी झंडी 8
- बिहार में अब 'मीठी क्रांति 9
- बिहार में 63 स्थानों पर बनाए जाएंगे नये आरओबी 10
- NIT पटना के छात्र द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को मिला पेटेंट 10
- बिहार के 10 शहरों के विकास के लिये बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी 11
- जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने ली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ 12
- पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिये जापान देगा 5509 करोड़ रुपए 13

नोट :

बिहार

बिहार की बबीता गुप्ता का 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023' के लिये चयन

चर्चा में क्यों ?

1 मार्च, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023' के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से आगामी चार मार्च को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023' से सम्मानित किया जाएगा।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के तहत चार मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा।
- विदित है कि प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर खुद की जीविका चलाने के साथ दूसरी महिलाओं को भी राह दिखा रहीं मुजफ्फरपुर की सीहो गाँव निवासी बबीता गुप्ता स्वयं सहायता समूह (जीविका) की सदस्य हैं और स्वच्छता तथा पेयजल के विभिन्न श्रेणियों के लिये हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उनका चयन किया गया है।
- पति की दिव्यांगता के बाद वह जीविका की सदस्य बनीं और प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने का हुनर जाना। इससे वह खुद स्वावलंबी बन चुकी हैं। अब वह गाँव की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी इस पहल से 24 से अधिक महिलाएँ आत्मनिर्भर हो चुकी हैं।

गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर (सीबीआईपी) द्वारा दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गू नदी पर बने गयाजी डैम को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह द्वारा दिया राष्ट्रीय पुरस्कार 'सीबीआईपी अवार्ड 2022' प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की उक्त दो योजनाओं के लिये पुरस्कार विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल और अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन ईश्वर चंद्र ठाकुर ने ग्रहण किया।
- राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली दोनों अतिमहत्त्वाकांक्षी योजनाएँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनूठी परिकल्पना और दूरदृष्टि का परिणाम हैं। इन योजनाओं का नाम 'गंगा जल आपूर्ति योजना'और 'गयाजी डैम'भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही रखा गया है।
- उन्होंने बताया कि गंगा जल आपूर्ति योजना के जरिये देश में पहली बार बाढ़ के पानी को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले प्रमुख शहरों में ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
- इसी तरह गया ज़िले में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निकट देश के सबसे बड़े रबर डैम के निर्माण से फल्गु नदी में आठ से दस फीट जल उपलब्ध है। पहले देश-दुनिया से पिंडदान एवं धार्मिक कार्य के लिये गया आने वाले लाखों श्रद्धालु फल्गु नदी के जल के लिये तरसते थे, लेकिन पिछले साल पितृपक्ष के दौरान आए करीब 12 लाख श्रद्धालुओं को फल्गु में लबालब जल रहने से काफी सुविधा हुई।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर (सीबीआईपी) द्वारा जल संसाधन, ऊर्जा और गैर-पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र की बेहतरीन परियोजनाओं को हर वर्ष 'सीबीआईपी अवार्ड'से सम्मानित किया जाता है।
- 'सीबीआईपी अवार्ड 2022 (जल संसाधन)' के लिये देशभर की जल संसाधन परियोजनाओं का चयन कुल दस श्रेणियों में किया गया है। इनमें बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित 'गंगा जल आपूर्ति योजना'और 'गयाजी डैम'का चयन 'जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन'जैसी अत्यंत महत्त्वपूर्ण श्रेणी में किया गया है।

पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हुआ आयोजन

चर्चा में क्यों ?

5 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार-गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह-2023 का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 150 महिलाओं को अपनी अनुकरणीय भूमिका से समाज में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित करने के लिये सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

नोट :

- कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे झिझिया और महिलाओं के लिये रनवे वॉक का भी आयोजन हुआ। इसके अलावा लेट्स इंस्पायर बिहार के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सदस्य, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिये काम किया, वैसे लोगों को भी सम्मानित किया गया।
- गार्गी उत्कृष्टता पुरस्कार नोएडा, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, बेंगलुरु, दिल्ली तथा देश से बाहर रह रही बिहारी महिलाओं को भी दिया गया। इसके अलावा बिहार से मिसेज केनिया रह चुकीं रूही सिंह, लंदन से एडवोकेट इलियास फातिमा, बेंगलुरु की फैशन डिजाइनर नीमा कुमार, मुंबई से एक्ट्रेस ऋषिका सिंह चंदेल, लोक गायिका हेमा पांडेय को गार्गी अवार्ड दिया गया।
- कार्यक्रम के दौरान आईपीएस विकास वैभव ने सभी महिलाओं को सम्मानित कर बिहार में आम लोगों के सामने उनका उदाहरण प्रस्तुत किया।
- इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिंदु ज्योति झा द्वारा लिखित और हेमंत झा द्वारा निर्देशित उपन्यास पर आधारित नाटक 'आनंदी'था, जिसे मुख्य अभिनेत्री मोना झा ने निभाया। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से महिलाओं द्वारा बिहारी भोज्य सामग्रियों तथा आर्ट-क्राफ्ट का स्टॉल भी लगाया गया।
- लेट्स इंस्पायर बिहार का कहना है कि हमारा उद्देश्य समाज की महिलाओं को एक मंच देकर उनका उत्थान करना है, जिससे वे एक चेंजमेकर के रूप में अभिनय करके प्रेरित कर सकें और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकें।
- शिक्षा, समता, उद्यमिता, समाज सेवा, कला संस्कृति, खेल जगत, अभिनय, साहित्य, चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को यह सम्मान उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया गया।

राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना

चर्चा में क्यों ?

5 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिये राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में खिलाड़ियों के चयन के लिये राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है।
- इस समिति के तहत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा चिह्नित खेलों के अंतर्गत भारत में संचालित राष्ट्रीय खेल महासंघों, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आदि संगठनों द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन होगा।
- मैडल विजेता खिलाड़ियों को 29 अगस्त को हर साल होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।
- राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मैडल जीतने वाले खिलाड़ी को दो करोड़, सिल्वर मैडल जीतने वाले को डेढ़ करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को एक करोड़ रुपए मिलेंगे।
- एशियन गेम्स में गोल्ड मैडल जीतने वाले को डेढ़ करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को एक करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए दिये जाएंगे।
- आधिकारिक एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल जीतने वालों को 75 लाख, सिल्वर जीतने वोले को 50 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख मिलेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीतने वाली भारतीय टीम में यदि बिहार के खिलाड़ी हैं तो उन्हें भी राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। वर्ल्ड कप या टी-20 की विजेता या उपविजेता भारतीय टीम में बिहार के कोई खिलाड़ी हैं, तो उन्हें क्रमश: सरकार डेढ़ और एक करोड़ देगी।
- राज्य सरकार चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता और उपविजेता टीम के बिहारी सदस्य को क्रमश: एक करोड़ और 75 लाख मिलेंगे तथा राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय खेल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को चार लाख, तीन लाख और दो लाख रुपए देगी।

नोट :

प्रदेश के 33 ज़िलों में खुलेंगे खेलो इंडिया के सेंटर

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार खेलों को बढ़ावा देने के लिये बिहार के 33 ज़िलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- खेलो इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि खेलो इंडिया योजना के तहत हर ज़िले में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जएगा।
- खेल वर्ग और ट्रेनिंग सेंटर-
  - वुशू - इंडोर स्टेडियम, पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, पटना
  - एथलेटिक्स - सरस्वती निवास, मंझोला, मुज़फ्फरपुर, न्यू स्टेडियम, फजलगंज, सासाराम पटेल फील्ड, समस्तीपुर, कोसी हाईस्कूल प्ले ग्राउंड, बिरपुर, सुपौल, नेहरू स्टेडियम, लहेरियासराय, दरभंगा
  - बैडमिंटन - कलेक्ट्रिएट कैंपस, अररिया, सहरसा
  - खो-खो - आरएचएमटीबी हाईस्कूल बरारी, भागलपुर, पुरानी बाज़ार वार्ड-12 सूरजपुर, लखीसराय, इंडोर स्टेडियम, मुंगेर
  - रग्बी - कपटिया, नालंदा
  - कुश्ती - कुवारिद्दी भोर, गोपालगंज, इंडोर स्टेडियम औरंगाबाद
  - तीरंदाज़ी - वीर कुँवर सिंह स्टेडियम, आरा, खरारी, गया।
  - कबड्डी - मिनता खेल परिसर, मकदुमपुर, शेखपुरा, वार्ड-16 रामपुर परोरी, सीतामढ़ी, हाईस्कूल अमैन, पारसबिगहा, जहानाबाद, बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम, मधेपुरा, महात्मा गांधी हाईस्कूल, बिहट, बेगूसराय, ब्रह्मपुर, बक्सर
  - फुटबॉल - महाराजा स्टेडियम, बेतिया, जगजीवन स्टेडियम, भभुआ, लक्ष्मीपुर, सितोपुर, सिवान
  - हॉकी - कोसी कॉलेज खगड़िया, श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम, जमुई, गोरौल हॉकी ग्राउंड, वैशाली वेटलिफ्टिंग कटिहार
  - टेबल टेनिस - वाटसन स्कूल, मधुबनी, तलवारबाज़ी - खेल भवन शाह व्यामशाला, मोतिहारी

अररिया में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर को बनाने का मास्टर प्लान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सेंट्रल जू आथॉरिटी) को भेजा जाएगा। इसके लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तैयारी कर रहा हैं।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि राज्य के दूसरे चिड़ियाघर को बनाने के मास्टर प्लान को अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक के दौरान अपनी मंज़ूरी दी थी।
- स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा मंज़ूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव सेंट्रल जू आथॉरिटी को भेजा गया था। इसके बाद से विभाग और सेंट्रल जू आथॉरिटी के बीच लगातार बातचीत जारी है। आथॉरिटी ने प्रस्ताव के बारे में जिन सवालों की जानकारी मांगी थी, उनके जवाब की तैयारी विभाग ने कर ली है।
- जानकारी के अनुसार अररिया ज़िले के रानीगंज में प्रस्तावित चिड़ियाघर का इलाका करीब 289 एकड़ में फैला हुआ है। यह स्थान नेपाल और पश्चिम बंगाल के नज़दीक है। ऐसे में वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी आते रहते हैं।

नोट :

- प्रस्तावित चिड़ियाघर के इलाके में तालाबों की बहुतायत होने से हर साल के अक्टूबर और मार्च महीने में प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। इस स्थान की आबोहवा शेर, बाघ, तेंदुआ, गैंडा, जिराफ, हिरण सहित अन्य जानवरों के लिये अनुकूल रहने की संभावना है। इस कारण विभाग ने इसे चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

विश्वस्तरीय बनेगा बिहार का मुज़फ्फरपुर रेलवे जंक्शन

चर्चा में क्यों ?

12 मार्च, 2023 को रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक पी.आर. सिंह ने बताया कि राज्य की राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुज़फ्फरपुर स्थित रेलवे जंक्शन को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक पी.आर. सिंह ने बताया कि मुज़फ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्वस्तरीय बनाने का यह काम दो फेज में किया जाएगा। प्रथम फेज का काम 2024 में पूरा कर लिया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मुज़फ्फरपुर के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिये सभी प्रकार की आधुनिक सेवाएँ बहाल की जाएंगी। यात्री सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। रेलवे जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ होंगी। मुज़फ्फरपुर जंक्शन उत्तर बिहार का सबसे बेहतरीन जंक्शन बनेगा।
- जानकारी के मुताबिक इसमें मल्टी स्टोरी पार्क्रिंग, एयर कॉनकोर्स, कंबाइंड टर्मिनल के अलावा प्रवेश व निकास वाले यात्रियों के लिये अलग-अलग भवन बनकर तैयार हो जाएंगे।
- वहीं द्वितीय फेज़ के तहत सितंबर 2025 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। इससे मुज़फ्फरपुर जंक्शन नए लुक में नज़र आएगा।
- संयुक्त महाप्रबंधक ने बताया कि स्टेशन के विकास पर कुल 446 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। एयरपोर्ट की तरह जंक्शन पर यात्री सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसके लिये एलिवेटेड सड़क, एस्कलेटर, लिफ्ट, टिकट व इंजीनियरिंग टर्मिनल और मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा।

नोट :

बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन-2015 लागू हो गया। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के लागू होने की जानकारी पटना उच्च न्यायालय को दी है। इसके लागू होते ही अब बिहार में फॉर्मा क्लीनिक खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। इस क्लीनिक के खुलने से दवाखाने में विक्रेता दवाओं की जानकारी देने पर शुल्क वसूल सकेंगे।
- विदित है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 और संशोधन 2021 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। यह कानून अभी देश के तीन राज्यों- केरल, कर्नाटक और दिल्ली में लागू है।
- उल्लेखनीय है कि यह रेगुलेशन भारत के राजपत्र में 16 जनवरी, 2015 को ही अधिसूचित किया गया।
- ज्ञातव्य है कि इस रेगुलेशन को लागू करने के लिये बिहार के एक फार्मासिस्ट मुकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहाँ से पक्ष में फैसला नहीं आने पर सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय को बिहार में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसे देखने का निर्देश दिया। इसी क्रम में राज्य सरकार ने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने संबंधी आदेश जारी कर दिया।
- बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया कि इस केंद्रीय विधान के प्रभाव में आते ही बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली प्रभावहीन हो गई है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के लागू होने से फार्मेसी निर्देशालय के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
- फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट और औषधि सूचना भेषजज्ञ के पदों का सृजन होगा। साथ ही इन विभिन्न पदों की योग्यता, इनका प्रयोजन, कर्तव्य, पर्यवेक्षण, औषधियों का उचित भंडारण, प्रबंधन, वितरण, उचित उपयोग, रोगी की देखभाल, समीक्षा मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश दिया गया है।
- इसके अंतर्गत सृजित पदों का कार्यस्थल भी तय होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस रेगुलेशन के अक्षरश पालन होने से स्वस्थ बिहार की कल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।
- फार्मेसी प्रैक्टिस हेतु फार्मासिस्टों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार चार समूह (कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट) में बाँटा गया है।
- धारा - 5 के अनुसार राज्य फार्मेसी काउंसिल राज्य में दवा निर्माण और वितरण के स्थलों की जाँच कर सकता है। दवा निर्माण और वितरण वाले स्थल पर फार्मासिस्ट कार्यरत हैं कि नहीं, इसकी जाँच कर इसकी सूचना काउंसिल के निबंधक के माध्यम से राज्य व केंद्रीय फार्मेसी काउंसिल को सूचना दी जानी है। इससे अवैध दवा कारोबार पर भी अंकुश लगेगा।

बिहार में 557 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मिली प्रारंभिक हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

18 मार्च, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 46वीं बैठक में 60 निवेश प्रस्तावों के तहत 557 करोड़ रुपए के निवेश को प्रारंभिक हरी झंडी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- ये सभी प्रस्ताव दो करोड़ रुपए से अधिक के हैं। इनमें सर्वाधिक 122 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिये है।

नोट :

- इसके अतिरिक्त इस बैठक में 13 प्रस्तावों को वित्तीय इंसेंटिव क्लियरेंस भी दी गई। इसके तहत 44 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बैंकों ने इनके लिये वित्तीय सुविधा, मदद और कर्ज उपलब्ध कराने की रजामंदी दे दी है।
- आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य के औद्योगिक इकाइयों की स्थिति मानचित्र पर अंकित करने के लिये कहा गया है साथ ही इंडस्ट्रियल शेडी ज़ोन को चिह्नित करने के निर्देश भी दिये गए हैं।
- 60 निवेश प्रस्तावों में 18 यूनिट राइस मिलों की स्थापना की हैं। यह सब यूनिट उसना चावल बनाने के लिये हैं। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार ने उसना चावल को प्रमोट किया है, लिहाजा ये निवेश प्रस्ताव आए हैं। ये सभी निवेश प्रस्ताव लखीसराय, अररिया, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, पटना, पश्चिमी चंपारण ज़िले में केंद्रित हैं।
- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रारंभिक क्लियरेंस पाने वाले 19 प्रस्ताव बाँका, वैशाली, पूर्णिया मुजफ्फरपुर, पटना, गया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई में केंद्रित हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य यूनिट स्थापना के लिये महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों में मुजफ्फरपुर स्थित मोतीपुर मेगा फूड पार्क में पॉल्ट्रीफीड के लिये करीब 18 करोड़ रुपए, पूर्णिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में 50 करोड़ रुपए का पोल्ट्री फीड प्लांट स्थापित किया जाना है।
- हाजीपुर इंडस्ट्रियल जोन में कुरकुरे और पोटेटो चिप्स के लिये 33 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त टैक्सटाइल सेक्टर में मुजफफरपुर में 40 करोड़ रुपए और करीब पौने तीन करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।
- पटना के दीघा आशियाना रोड पर 150 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना में 58 करोड़ रुपए, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना में आइटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स आदि से जुड़े हार्डवेयर के निर्माण के लिये 19 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 17.38 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होटल और बेनक्वेट के निर्माण पर प्रस्तावित है।
- मुख्य प्रस्ताव जिन्हें फाइनेंसियल इंसेंटिव दिया गया-
  - बक्सर में 65 केएलपीडी का इथेनॉल प्लांट
  - राजेंद्र नगर रोड पटना में 73 बेड का मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पीटल
  - बाँका ज़िला स्थित अमरपुर में एलपीजी बॉटलिंग रेफलिंग प्लांट
  - गया में रेनेवल एनर्जी सेक्टर में 1500 केडब्ल्यूपी की नयी ग्रिड
  - फतुहा में एक लाख मीटरिक टन वार्षिक उत्पादन वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट
- सेक्टर वाइज निवेश प्रस्ताव जिन्हें स्टेज वन क्लियरेंस दी गई है-

सेक्टर	आवेदनों की संख्या	कुल प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
राइस मिल	19	103
फूड प्रोसेसिंग	18	225
जनरल मैन्युफैक्चरिंग	12	64.59
टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज	2	42.20
अदर्स इंडस्ट्रीज	9	122.32

बिहार में अब 'मीठी क्रांति

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मीठी क्रांति (शहद उत्पादन) को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार ने राज्य के 17 ज़िलों का चयन किया है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहर मिशन (नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन) के तहत इनका चयन किया गया है। योजना क्रियान्वयन के लिये इन ज़िलों को राशि की पहली किस्त भी भेजी जा रही है। केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ स्वीकृत किये हैं।

नोट :

- बिहार में औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली ज़िलों का चयन किया गया है। यहाँ हनी मिशन यानि मीठी क्रांति की सफलता के लिये केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से काम करेंगी।
- मधुमक्खी पालन में राज्य में महिलाओं के समूह, जीविका और वेजफेड को प्राथमिकता दी जाएगी। 30 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। इसका फायदा जीविका दीदियों को भी मिलेगा। महिला समूहों, किसान समूहों, सहकारी समितियों को अनुदान देकर इसके लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिये बढ़ावा देने के अलावा तकनीकी सहायता और आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में फूल वाले पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि इसमें खर्च किया जाएगा।
- राज्य सरकार की ओर से इसमें वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। ज़िला बागवानी विकास समिति को किसान समूह चयन की जिम्मेवारी दी गई है।
- इस योजना का उद्देश्य मधु क्रांति यानि मीठी क्रांति लाना है। मधु क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन, मधु उत्पादन एवं अन्य उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि एवं गैर कृषि परिवार को रोज़गार दिलाने में भी यह मदद करेगा।
- विदित है कि बिहार में बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन होता है। राज्य के करीब पचास हज़ार लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिहार के शहद की देश ही नहीं बल्कि विदेशों (अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, मोरक्को) में भी ज्यादा मांग है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहर मिशन शुरू होने का फायदा यहाँ के मधुमक्खी पालकों को होगा।

बिहार में 63 स्थानों पर बनाए जाएंगे नये आरओबी

चर्चा में क्यों ?

21 मार्च, 2023 को बिहार के राजस्व, भूमि सुधार और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान राज्य में 63 स्थानों पर नये रेलवे उपरगामी सेतु (आरओबी) बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि आरओबी हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि जीएडी अनुमोदन और डीपीआर बनाई जा रही है। अभी रेलवे के प्रस्तावित आरओबी में से 47 को जीएडी ने अनुमोदित कर दिया है। इसमें से 13 आरओबी की डीपीआर पर रेलवे ने अनुमति दी है। इसी क्रम में समस्तीपुर रेल मंडल में दलसिंह सराय और नासिरगंज के बीच आरओबी बनाया जाएगा।
- इस अवसर पर मंत्री आलोक मेहता ने 2023-24 के लिये नयी परियोजनाओं की घोषणा की-
  - जेपी गंगा पथ से दीघा से शेरपुर तक 50 किमी. लंबा सिक्स लेन - 3100 करोड़ रुपए।
  - दीघा से एएन सिन्हा तक के रास्ते में रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट एवं सौंदर्यीकरण - 500 करोड़ रुपए।
  - करौटा-तेलमर पथ के मार्ग में नूरसराय से सिलाव तक 60 किमी. लंबा फोर लेन ग्रीन फील्ड योजना - 862 करोड़ रुपए।
  - राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने और क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण - 1600 करोड़ रुपए।
  - कोशी नदी पर डेंगराहीघाट पुल का निर्माण - 415 करोड़ रुपए।

NIT पटना के छात्र द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को मिला पेटेंट

चर्चा में क्यों ?

23 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एनआईटी पटना के पीएचडी स्टूडेंट्स डॉ. हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन, जो मेटेरियल के सैंपल के आधार पर सड़क की निर्माण सामग्री में नमी की पहचान कर लेगी, को पेटेंट मिल गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पीएचडी स्टूडेंट्स डॉ. हिलोल चक्रवर्ती ने बताया कि सिमुलेटर मशीन से अलकतरा के साथ कौन-सा मेटेरियल मिलाया जाए, जिससे सड़क पानी या अधिक गर्मी या फिर अधिक दबाव से जल्दी खराब न हो, इसकी पहचान की जाएगी।
- यह मशीन मौसम, वाहनों के दबाव और पथरीले स्थान पर अलकतरा के साथ सीमेंट या अन्य सामग्री कितना और कैसे मिलाया जाएगा, यह बताएगी।
- विदित है कि एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र डॉ. हिलोल चक्रवर्ती ने चार साल के रिसर्च के बाद सिमुलेटर मशीन को बनाया है।
- एनआईटी के डीन प्रो संजीव सिन्हा ने बताया कि उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से सड़क हर साल खराब हो जाती है। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मशीन की सहायता से सड़कें जल्दी खराब नहीं होंगी, क्योंकि पहले इसके कारणों का पता लगाकर सड़कें बनाई जाएंगी।
- उन्होंने बताया कि नयी तकनीक के आधार पर सड़क निर्माण सामग्री की जाँच करने की यह पहली मशीन है और यह बहुत ही कम लागत में बनाई गई है।
- अब सिमुलेटर मशीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिये किसी कंपनी या सरकार के साथ समझौता किया जाएगा। पानी और अन्य कारणों की वजह हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से सड़क जल्दी खराब नहीं होगा।

डॉ. हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन

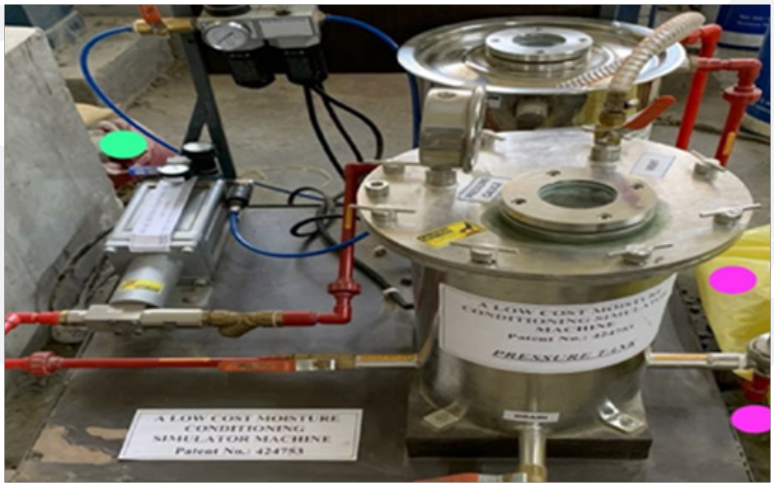

बिहार के 10 शहरों के विकास के लिये बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी

चर्चा में क्यों ?

28 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने दस नये विस्तारित शहरों की प्लानिंग एरिया अथॉरिटी (आयोजना क्षेत्र प्राधिकार) को अधिसूचित कर दिया है, जिनमें नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- नये विस्तारित शहरों की प्रत्येक प्लानिंग एरिया अथॉरिटी में संबंधित ज़िले के डीएम अध्यक्ष, जबकि संबंधित प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य सचिव बनाए गए हैं।

नोट :

- इनके अलावा, संबंधित ज़िले के उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), पथ निर्माण, पीएचईडी और ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित क्षेत्र में आने वाले नगर निकाय के कार्यपालक अभियंता, मुख्य नगर निवेशक तथा क्षेत्रीय निवेश संगठन या उनके प्रतिनिधि और नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अथॉरिटी का पदेन सदस्य बनाया गया है।
- प्लानिंग एरिया अथॉरिटी पर विस्तारित क्षेत्र के लिये मास्टर प्लान के साथ ही अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके क्रियान्वयन और अन्य नियमानुकूल कार्रवाई की जिम्मेदार होगी। इससे संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिये नक्शा भी अथॉरिटी ही पास करेगी।
- विदित है कि विभाग ने करीब दो महीने पहले ही संबंधित निकाय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों को जोड़कर इन 10 आयोजना क्षेत्रों को अधिसूचित किया था। अब अथॉरिटी बनने से इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में पहले से 33 प्लानिंग एरिया अथॉरिटी अधिसूचित हैं। दस नये प्लानिंग एरिया की अथॉरिटी अधिसूचित होने पर इनकी कुल संख्या बढ़कर 43 हो गई है।
- अधिकारियों के मुताबिक प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के फंक्शनल होने से संबंधित क्षेत्र का शहरीकरण तेज होगा और उनमें व्यावसायिक व आवासीय गतिविधियाँ बढ़ेंगी।
- डीएम की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी सबसे पहले सर्वे कर क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करेगी। फिर इलाके की विशेषताओं के मुताबिक शहरीकरण के तत्त्वों को बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत चयनित बड़ी योजनाओं की अनुशंसा राज्य सरकार से की जाएगी ताकि उसके लिये आवश्यक राशि का प्रबंध किया जा सके।
- राज्य के इन 43 नये शहरों में प्लानिंग अथॉरिटी गठित की गई है, जिसके अंतर्गत आरा, अररिया, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, बिहारशरीफ, बोधगया, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, राजगीर, सहरसा, सासाराम, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल ज़िले शामिल हैं।

जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने ली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जस्टिस के. विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 26 अप्रैल, 2025 को जस्टिस के. विनोद चंद्रन रिटायर होंगे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि इससे पहले जस्टिस के. विनोद चंद्रन केरल हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के प्रमोशन के बाद उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है।
- गौरतलब है कि जस्टिस संजय करोल सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में 3 मुख्य न्यायाधीश, दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद के लिये की गई थी। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल भी उनमें शामिल हैं। इस वजह से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली था।
- उल्लेखनीय है कि जस्टिस के. विनोद चंद्रन 2011 के नवंबर महीने में केरल उच्च न्यायालय में जज बने थे।

नोट :

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिये जापान देगा 5509 करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिये 5,509 करोड़ रुपए देगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पटना मेट्रो रेल विकास (पीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक अरुणीश चावला (आईएएस) और शहरी विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- परियोजना का उद्देश्य नए मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 का निर्माण करके बिहार की राजधानी पटना में यातायात की मांग में वृद्धि को आसान करना है, जिससे शहरी पर्यावरण में सुधार और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित शहरी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया जा सके।
- यह परियोजना एसडीजी लक्ष्य 8, 9, 11 और 13 की उपलब्धि में योगदान देगी।
- योजना के अनुसार, जेआईसीए जून 2023 तक पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिये परामर्श सेवाएँ (निर्माण पर्यवेक्षण सहित) प्रदान करने के लिये सलाहकारों की नियुक्ति करेगा।
- परियोजना निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी के लिये प्रारंभिक खरीद पैकेज जून 2023 में शुरू किया जाएगा। ऋण राशि 30 वर्ष की छूट अवधि के साथ 10 वर्ष की चुकौती अवधि के लिये स्वीकृत की गई है।
- पटना मेट्रो का 14.05 किलोमीटर का कॉरिडोर-2 पटना रेलवे जंक्शन को पटना जंक्शन (कॉरिडोर-12 के साथ इंटरचेंज), आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, मोइन उल हाग स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, खेमनी चक (इंटरचेंज), भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू आईएसबीटी पर 1 स्टेशनों के साथ नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से जोड़ेगा।
- इनमें से 6 स्टेशनों के साथ 5 किलोमीटर खंड को अलग किया जाएगा और शेष 8 किलोमीटर खंड को 7 स्टेशनों के साथ भूमिगत किया जाएगा।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत 13,365.77 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के वर्ष 2028 तक चालू होने की उम्मीद है।
- पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के निकट बैरिया, संपतचक में पटना मेट्रो का डिपो होगा।

नोट :